भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 515
उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2025

तमिलनाडु में नए दूरसंचार टावर

515. श्री सी. एन. अन्नादुरईः
श्री जी. सेल्वमः
श्री नवसकनी के.:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में उन गाँवों, जहाँ विगत पाँच वर्षों के दौरान नए दूरसंचार टावर संस्थापित किए गए हैं, का वर्षवार और ज़िला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में यूएसओएफ, भारतनेट या 4जी संतृप्ति योजना जैसी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत संस्थापित टावरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या तमिलनाडु में, विशेषकर पहाड़ी, वनीय या जनजातीय क्षेत्रों में, अभी भी कोई गाँव मोबाइल नेटवर्क कवरेज से वंचित है और यदि हाँ, तो नवीनतम सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार ऐसे गांवों की संख्या और उनके नाम क्या हैं और इन गाँवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की समय-सीमा क्या है;

(घ) तमिलनाडु में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं के विस्तार में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की भूमिका क्या है;

(ङ) विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य में यूएसओएफ परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत और उपयोग की गई कुल राशि कितनी है; और

(च) इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले जिलों और गाँवों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) तमिलनाडु के गांवों जहां विगत पांच वर्षों के दौरान नए दूरसंचार टावर संस्थापित किए गए हैं, का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा, डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) [पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)] की वेबसाइट (https://usof.gov.in/en/home) पर उपलब्ध

है। तमिलनाडु में डीबीएन द्वारा वित्तपोषित 4जी सेचुरेशन स्कीम के तहत मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए कुल 256 टावर संस्थापित किए गए हैं। तमिलनाडु में मोबाइल कवरेज से वंचित 5 गाँवों का विवरण डीबीएन की वेबसाइट (https://usof.gov.in/en/home) पर उपलब्ध है।

(घ) तमिलनाडु में भारतनेट परियोजना के तहत कनेक्ट की गई ग्राम पंचायतों (जीपी) की संख्या और 4जी सेचुरेशन स्कीम के तहत कनेक्ट किए गए गांवों की संख्या डीबीएन की वेबसाइट (https://usof.gov.in/en/home) पर उपलब्ध है।

(ङ) तमिलनाडु राज्य के लिए विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान डीबीएन के माध्यम से वित्त पोषित विभिन्न स्कीमों के तहत 1,610.11 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

(च) डीबीएन परियोजनाओं से लाभान्वित जिलों और गांवों का विवरण डिजिटल भारत निधि की वेबसाइट (https://usof.gov.in/en/home) पर उपलब्ध है।

*****